



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—SECTION 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 284]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 16, 2018/श्रावण 25, 1940

No. 284]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 16, 2018/SHRAVANA 25, 1940

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 अगस्त, 2018

सं. 1(5)/2018-एसपी-1.—केंद्र सरकार ने गन्ने की लागत की भरपाई करने और चीनी मौसम 2017-18 के लिए किसानों को देय गन्ना मूल्य का समय से भुगतान सुनिश्चित करने की दृष्टि से दिनांक 09.05.2018 की अधिसूचना सं.1(5)/2018-एसपी-1 द्वारा चीनी मिलों के लिए सहायता की स्कीम अधिसूचित की थी।

2. अब दिनांक 09.05.2018 की उक्त अधिसूचना के पैरा 6 के अनुसरण में केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है कि अधिसूचना के पैरा 3 (v) को निम्नानुसार पढ़ा जाएः—

“यह सुनिश्चित करने के लिए कि सहायता की राशि किसानों के खातों में सीधे जमा कराई जाए, चीनी मिल राष्ट्रीयकृत बैंक/सहकारी बैंक में एक अलग नो-लियन(No-Lien) खाता खोलेगी और उक्त बैंक को किसानों के बैंक खातों के विवरण तथा उचित और लाभकारी मूल्य के संबंध में वर्तमान चीनी मौसम 2017-18 के लिए देय गन्ना मूल्य बकाया की सीमा और पिछले चीनी मौसमों की गन्ना मूल्य बकाया की राशि, जो संबंधित राज्य के गन्ना आयुक्त/शर्करा निदेशक द्वारा विधिवत प्रमाणित हो, की सूचना देगी।”

सुरेश कुमार वशिष्ठ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Food and Public Distribution)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 16th August, 2018

No. 1(5)/2018-SP-I.—Whereas the Central Government with a view to offset the cost of cane and facilitate timely payment of cane price dues of farmers for sugar season 2017-18, notified the Scheme for Assistance to Sugar Mills vide notification No. 1(5)/2018-SP-I dated 09.05.2018.

2. Now in pursuance of para 6 of the said notification dated 09.05.2018, Central Government has decided that Para 3(v) of the notification may be read as under:—

“In order to ensure that the assistance is directly credited into the accounts of farmers, the sugar mill shall open a separate no-lien account in a Nationalized bank/co-operative bank and furnish to that bank the list of farmers along with bank accounts details and extent of cane price dues payable for the current sugar season 2017-18 relating to FRP and cane price arrears of previous sugar seasons, duly certified by the Cane Commissioner/Director of Sugar of the state concerned.”

SURESH KUMAR VASHISHTH, Jt. Secy.